87. Selection Committee and its composition.- (1) The State Government 87. Selection Committee and shall constitute a Selection Committee for a period of three years by notification in

- (i) a retired judge of High Court as the Chairperson to be appointed in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned;
- one representative from the Department implementing the Act not below the rank of Director as the ex-officio Member Secretary:
- two representatives from two different reputed non-governmental organisations respectively working in the area of child development or child protection for a minimum period of seven years but not running or managing any children's institution;
- (iv) two representatives from academic bodies or Universities preferably from the faculty of social work, psychology, sociology, child development, health, education, law, and with special knowledge or experience of working on children's issues for a minimum period of seven years; and
- (v) a representative of the State Commission for Protection of Child Righls.
- (2) The Committee shall continue for a maximum period of three months after the completion of its tenure by which time new Committee shall be constituted.
- (3) If a vacancy arises in the Selection Committee, the Member Secretary shall intimate the Secretary of the Department implementing the Act who shall take steps to fill the vacancy for the remaining period at the earliest.
- (4) The quorum for the meeting of the Selection Committee shall be not less than four Members, including the Chairperson and the Member Secretary.
- (5) The Member Secretary of the Selection Committee shall convene the meetings of the Selection Committee at such times as may be necessary for facilitating and carrying out the functions of the Selection Committee.
- (6) The Member Secretary shall maintain the minutes of the selection process and all other meetings of the Selection Committee.
- (7) The Chairperson and non-official members of the Selection Committee shall be paid such sitting fees and travel allowances as may be fixed by the State

विधिक सेवा प्राधिकरण क राज्य ।। क सथा 87. चयन समिति और इसकी अवसंरचना.—(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 87. जन अविध के लिए चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:

- (i) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;
- (ii) पदेन सदस्य सचिव के रूप में अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे विभाग का एक प्रतिनिधि जो कि निदेशक के स्तर से नीचे का न हो;
- (iii) दो अलग-अलग प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन जो क्रमशः बाल विकास और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष से कार्य कर रहे हों लेकिन किसी भी बाल संस्था का प्रबंधन या संचालन नहीं कर रहे हों, के दो प्रतिनिधि;
- (iv) शैक्षणिक निकायों या विश्वविद्यालयों, अधिमानत: समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि संकाय से दो प्रतिनिधि जिनके पास बालकों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने का कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो; और
- (v) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक प्रतिनिधि।
- (2) समिति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अधिकतम तीन मास की अविध तक बनी रहेगी जिस समय तक नई सिमिति गठित हो जाएगी।
- (3) यदि चयन समिति में कोई पद रिक्त होता है, तो सदस्य सचिव अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग को सूचित करेगा जो शेष अविध के लिए रिक्त पद भरने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करेगा।
- (4) चयन सिमिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष और सदस्य सिचव सिहत चार सदस्यों से कम नहीं होगा।
- (5) चयन समिति का सदस्य सचिव चयन समिति की बैठकें ऐसे समय पर आहूत करेगा जो चयन समिति के कार्यों को सुकर बनाने और करने के लिए आवश्यक हो।
- (6) सदस्य सचिव चयन प्रक्रिया और चयन समिति की अन्य सभी बैठकों के कार्यवृत्तों को खिगा।
- (7) चयन समिति के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित बैठक शुल्क और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

- The Juv. Jus. (Care & Prot. of Children) Model Rules, 2016 [Rule 87-88 The Juv. Jus. (04) All communications relating to the working and discharge of the functions shall be addressed to the Office of the Member Sections (8) All communications relating to the model of the Selection Committee shall be addressed to the Office of the Member Secretary.
- Government Department concerned.
- 88. Selection of Chairperson and Members of the Committee or Board. 88. Selection of Chairperson and Chairperson a filling up a vacancy six months prior to the incumbent demitting office:

Provided that if a vacancy arises on account of resignation or death of the Provided that if a vacancy successful the Board or Committee the Member of the Board or Committee the Member of the Source Committee shall immediately initiate the provided Committee shall be provided committee shall b Chairperson of the Committee Shall immediately initiate the process for filling up such vacancy.

- (2) For selection of members of the Board or Chairperson and members of the Committee, the State Government through the Member Secretary of the Selection Committee shall call for applications through public advertisement in the local and national newspapers and official website of the Department implementing the Act,
- (3) The Member Secretary shall screen all the applications received and placethe applications which fulfil the basic eligibility requirements before the Selection Committee.
- (4) The Selection Committee shall evaluate the candidates on the basis of qualifications, experience of working with children and personal interaction with the candidate.
 - (5) A member selected by the Selection Committee should not:
 - (i) be holding such full-time occupation that may not allow the person to give necessary time and attention to the work of the Board or the Committee as per the Act and rules;
 - (ii) be associated with any Child Care Institution, directly or indirectly, during his tenure as a member of the Board or Committee or have any other conflict of interest.
 - (iii) hold any office in any political party during his tenure, or
 - (iv) be insolvent.
- (6) Where the Selection Committee is required to consider an application for renewal of tenure of Members of the Board or Committee as the case may be, it shall evaluate the application on the basis of the following criteria, namely:
 - regular performance appraisals of the Member carried out by the District Judge or District Magistrate quarterly as per a specified format, a copy of which shall be made available to the Chairperson and Members of the Selection Committee by the Member Secretary;
 - (ii) complaints if any, received and addressed by the Selection Committee against the person seeking an extension of tenure; and
 - interaction with such applicant.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (8) चयन समिति के कार्यकरण और कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी पत्राचार सदस्य

(8) विवास को संबोधित किए जाएंगे जो उन्हें चयन समिति के समक्ष रखेगा। व के कारण है। विकास सभी अभिलेख संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। (9) प्राप्त का वबसाइट पर डाल जाएग। कि. सिमित और बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन.—(1) सदस्य सिचव पदधारी 88. सामार के छह मास पहले से रिक्त होने वाले पद को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा : पदमार पद समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने या उसकी पूर्व पद समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने या उसकी परत थाप पर देने या उसकी परत सीमित का सदस्य सिचव ऐसे रिक्त पद को भरने की मृत्यु होने के कारण रिक्त होता है तो चयन सिमित का सदस्य सिचव ऐसे रिक्त पद को भरने की

प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगा। (2) बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए, राज्य सरकार चयन (2) नार्पार प्रथम सिव्यं के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और अधिनियम का सामात पर राज्य न आर आधानयम का सामात पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कार्यान्वयन करने वाले विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित

(3) सदस्य सचिव प्राप्त हुए सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और उन आवेदनों को जो पात्रता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

 (4) चयन सिमिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अध्यर्थों के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी।

(प्रीड) चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य:

- (i) ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमित न देता हो;
- (ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो;
- (iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो;
 - (iv) दिवालिया न हो।
- (6) जिस मामले में चयन सिमिति को यथास्थिति बोर्ड या सिमिति के सदस्यों के कार्यकाल के नवीकरण के आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता हो, उस मामले में चयन समिति आगे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी, अर्थात् :
 - (i) विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए सदस्य के नियमित तिमाही निष्पादन मूल्यांकन, जिनकी प्रति सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी; (ii) कार्यकाल के विस्तार का आवेदन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चयन समिति को
 - यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो वह शिकायत; और
 - (iii) ऐसे आवेदक के साथ विचार-विमर्श।

The Juv. Jus. (Care & Prot. of Children) Model Rules, 2016 [Rule 88] The Juv. Jus. (Care & Pro. (7) The Selection Committee shall, on the basis of the evaluation procedure select and recommend a panel of names in order of merit to the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Surant as Members of the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of the Board or Chairperson and the Surant as Members of (7) The Selection Committee shall, of this basis of the evaluation procedulation, select and recommend a panel of names in order of merit to the same and criteria, select and recommend as Members of the Board or Chairperson or Machine States. (7) The select and recommend a parish of the Board or Chairperson or Ment to the Soverment for appointment as Members of the Board or Chairperson or Ment to the Soverment for appointment as the case may be. of the Committee as the case may be.

(१८) चयन समिति बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के ती मामला हो, मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर केट में नियुक्ति के (7) चयन सानार । (7) चयन सानार हो, मृल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर पैनल में से नामों का चयन हिए क्यांका राज्य सरकार को करेगी। लिए जर्मा और सिफारिश राज्य सरकार को करेगी।

(8) In recommending a panel of names, the Selection Committee shall prepage of names and respectively. of the Commending a panel of names, the Selection Committee shall preparate panels for the position of Chairperson of the Committee, Members of the Board respectively.

्रिस्कारिश राज्य ते. (8) नामों के पैनल की सिफारिश करते समय चयन समिति समिति के अध्यक्ष, समिति के (8) नामों के सदस्यों के पदों के लिए अलग-अलग पैनल नैगए नोजी (8) नामा च बोर्ड के सदस्यों के पदों के लिए अलग-अलग पैनल तैयार करेगी।

mittee and Members of the Board responsible.

(9) The Selection Committee shall prepare a three member panel for each position, which shall be vaild for a period of one year.

ह्यों और बार्ड पर पर कि लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जोकि एक वर्ष की

(9) चयन समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(10) The list of finalised names shall be duly signed by all members of the Committee present at the time of selection and the Member Secret. (10) The list of finalised names snall be duly signed by all members of the Selection Committee present at the time of selection and the Member Secretary of the Committee shall forward the finalised list to the State Government. selection Committee present at the time of selection and the intermed Secretary of the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government one or more Board for the Selection Committee shall constitute one or more Board for the Selection Committee shall constitute one or more Board for the Selection Committee present at the time of selection and the intermed selection Committee present at the time of selection and the intermed selection Committee present at the time of selection Committee present at the time of selection Committee shall forward the finalised list to the State Government on the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government on the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government on the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government on the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government on the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government on the Selection Committee shall be selected by the Selection the Selection Committee shall forward the images and the State Government shall constitute one or more Boards or appointment. The State Government shall constitute one or more Boards or appointment. appointment. The State Government small consults one or more Boards or Committees, as the case may be, in each district through notification in Official commendations of call find months of receipt of recommendations of call Committees, as the case may be, in each district an additional in Official Gazette within a period of two months of receipt of recommendations of Selection

धि के लिए न अंतिम रूप से निर्धारित नामों की सूची पर चयन के समय मौजूद चयन समिति के सभी (10) अंतिम रूप से निर्धारित करेंगे और सदस्य सचिव अंतिम रूप से नैक्स करें (10) आवन रेने अप सदस्य सचिव अंतिम रूप से तैयार सूची को नियुक्ति के सभी सदस्य की को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्थित एक स्वास्थित के लिए सहस्य निष्यत एउन ने राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्यित एक या एक से अधिक बोर्डों या राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्यित एक या एक से अधिक बोर्डों या राज्य सरकार का निर्माण स्थाप सिमिति की सिफारशों की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि में _{राजपत्र} में अधिसूचना द्वारा करेगी।

nittee.

(11) Names on the panel shall be valid for consideration for a period of one panel has not to the panel h (11) Names on the pariet shall be valid for the state of the pariet of one year which may be extended by six months where a new panel has not yet been year which may arise during such positive been the state of the pariet been the par year which may be extended by six months which may arise during such period either constituted, in order to fill in vacancies which may arise during such period either to the constituted time from the constituted, in order to ill in vacanicles which that a stipulated time from the date due to non-reporting of the selected persons within a stipulated time from the date of appointment, or otherwise during the tenure of the Board or Committee.

(11) ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए, जो ऐसी अविध में बोर्ड या समिति के कार्यकाल के (11) एत पा सामात क कायकाल के हौरान या तो चयनित व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति को तारीख से निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होतन या ता अन्याया रिक्त पदों को भरने के लिए नामों पर विचार करने के लिए पैनल में दिए होने के कारण जा जार का लिए वैध होंगे जिसे छह मास की अविध के लिए बढ़ाया जा मकेगा जहां पर नया पैनल उस समय तक तैयार नहीं किया गया है।

(12) If a vacancy in the Board or Committee arises, the District Child Protection Unit shall inform the State Government for filling up such vacancy.

(12) यदि बोर्ड या समिति में कोई पद रिक्त होता है, जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(13) The State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee within a period of three months from receiving such information from the District Child Protection Unit.

(13) राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन मास की अवधि के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए गए नामों के पैनल के आधार पर रिक्त पर्दों को

(14) If any complaint is made against a member of the Board or Committee, the State Government shall hold necessary inquiry except in respect of judicial officers; complaints against judicial officers shall be forwarded to the Registrar of

... (14) यदि बोर्ड या सिमिति के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों से संबंधित शिकायतों के अलावा, आवश्यक जांच करायेगी; न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय के रिजस्ट्रार को अग्रेपित की जाएंगी।

(15) The State Government shall complete the inquiry within a period of one month and take appropriate action within two months.

(15) राज्य सरकार एक मास की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी और दो मास के भीतर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

(16) If a criminal case is registered against the person concerned, Government may suspend the appointment for such term as appropriate after due inquiry.

(16) यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, सरकार यथोचित र्णंच के बाद ऐसी अविध के लिए नियुक्ति को निलंबित कर सकती है।

89. Training of Personnel Dealing with Children.- (1) The State Government shall provide for training of personnel appointed under the Act and the rules and each category of staff, keeping in view with their statutory responsibilities and specific

89. बालकों से ब्यौहार कर रहे कार्मिकों का प्रशिक्षण.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए और कर्मचारीवृंद के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्टित: कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देगी।

(2) The training programme shall include:

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(i) introduction of the Act and the rules made thereunder;

(i) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रस्तावना; (ii) बाल कल्याण, देखरेख, संरक्षण और बाल अधिकार पर अभिविन्यास;

orientation on child welfare, care, protection and child rights; induction training of the newly recruited personnel; (iii)

(iii) नए भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रतिस्थापना प्रशिक्षण;

(iv) refresher training courses and skill enhancement programmes, documentation and sharing of good practices; and

(iv) पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, प्रलेखाकरण और अच्छी पद्धतियों की साझेदारी; और